पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International Since 1983

हमारा मुख-पत्र वर्ष 26, अंक 4/2025

राष्ट्रीय राजमार्गः स्पीड कॉरिडोर से ज्यादा 'मौत के गलियारे'

भारत में सड़क सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। वर्ष 2023 में देशभर में 4.61 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें से 1.72 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि देश के सड़क नेटवर्क का केवल 2 प्रतिशत हिस्सा- राष्ट्रीय राजमार्ग ही कुल मौतों के 30-35 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारत के राजमार्ग अब 'मौत के गलियारे' बनते जा रहे हैं।

भारत में 2023 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं 29.8 प्रतिशत और मौतें 35.2 प्रतिशत हुई हैं। राजस्थान में विगत कुछ दिनों में भीषण सड़क हादसे हुए हैं। इनमें 2 नवंबर को फलोदी (जोधपुर) के भारतमाला हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक टेम्पो ट्रैवलर, जो तीर्थयात्रियों को लेकर लौट रही थी, सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जबकि 2-3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वैसा ही लोमहर्षक हादसा 3 नवंबर को नेशनल हाईवे के निकट लोहा मंडी-सीकर रोड, हरमाड़ा में हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये घटनाएं राज्य में सड़क सुरक्षा की गंभीर स्थिति को दर्शाती हैं और यातायात नियमों के कड़े पालन की आवश्यकता पर बल देती हैं। भारत में राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिनके पीछे कई प्रमुख कारण हैं। सबसे बड़ा कारण अधिक गति है- कुल दुर्घटनाओं में लगभग 66.5 प्रतिशत हादसे और 72.3 प्रतिशत मौतें इससे जुड़ी पाई गई हैं। इसके अलावा, चालकों की थकान और ध्यान विचलन भी एक गंभीर समस्या है। तीसरा प्रमुख कारण है खराब सड़क अभियांत्रिकी, जिसमें तीखे मोड़, अंधे मोड़ और अपर्याप्त संकेत शामिल हैं। कमजोर प्रवर्तन भी एक अहम कारण है-ट्रैफिक नियमों के ढीले पालन और सीमित स्पीड कैमरों के कारण नियमों का प्रभावी अनुपालन नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त शराब या नशे की हालत में ड्राइविंग, तथा धुंध या बारिश जैसी खराब दृश्यता की स्थिति, हादसों को और बढ़ाती है।

सड़क सुरक्षा के लिए केवल अवसंरचना का विकास ही नहीं, बल्कि सख्त प्रवर्तन और जनजागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। भारत सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें अवैध सड़क अतिक्रमण हटाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश, साइड रोड डिजाइन, संकेतों तथा मर्जिंग लेन में सुधार और ब्लैक स्पॉट की पहचान एवं सुधार कार्यों में तेजी लाना जैसी कार्रवाई शामिल हैं।

हालांकि इन पहलों के बावजूद, राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। यह दर्शाता है कि सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में केवल नीतिगत प्रयास पर्याप्त नहीं हैं- इन्हें प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और जनजागरूकता पर भी समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। सड़क सुरक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए कुछ राज्यों ने समर्पित हाईवे ट्रैफिक पुलिस बल की स्थापना की है।

महाराष्ट्र इस दिशा में एक अग्रणी उदाहरण है, जहां एक विशेष राजमार्ग पुलिस बल कार्यरत है। इस बल में 2,000 से अधिक कर्मचारी तैनात हैं, जो राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर निरंतर गश्त और निगरानी रखते हैं। महाराष्ट्र का मॉडल अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर सड़क सुरक्षा प्रवर्तन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरे राज्यों में यह जिम्मेदारी राज्य पुलिस और यातायात विभाग निभा रही हैं। भारत में अब तक एक एकीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा बल का गठन नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 'स्पीड मैनेजमेंट गाइडलाइंस' शीघ्र लागू नहीं की गई, तो सड़क सुरक्षा पर किए जा रहे सभी प्रयास अधूरे रह जाएंगे।

सड़क सुरक्षा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कुछ कदम तत्काल उठाए जाने आवश्यक हैं। सबसे पहले, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन शीघ्र किया जाना चाहिए, ताकि सड़क सुरक्षा से जुड़ी सभी नीतिगत, तकनीकी और संस्थागत एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। दूसरा, देश के लिए एक राष्ट्रीय गति प्रबंधन दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए, जिनके अंतर्गत स्पीड मॉनिटरिंग, कैमरा-आधारित प्रवर्तन और स्वचालित दंड प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके। तीसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य परिवहन विभाग और राज्य सरकारों के बीच नियमित संयुक्त समीक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, जिससे सड़क सुरक्षा योजनाओं, ब्लैक स्पॉट सुधार कार्यों और प्रवर्तन गतिविधियों की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित हो सके। इन कदमों से केंद्र और राज्य स्तर पर समन्वित प्रयासों को बल मिलेगा और सड़क सुरक्षा लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी आएगी।

यदि सड़क अभियांत्रिकी, प्रवर्तन, और जन-जागरूकता में ठोस सुधार नहीं हुए, तो ये 'विकास के राजमार्ग' आगे भी 'मौत के राजमार्ग' बने रहेंगे।

प्रदीप एस महता

महामंत्री, कट्स इंटरनेशनल

इस अंक में...

- करोड़ों रुपए खर्च फिर भी परियोजनाएं रही अधूरी ... 3
- सरकार को लगाई 600 करोड़ की चपत ... 4
- नीतियों की नई उड़ान, प्रदेश बनेगा विकास का हब . 7
- सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर ... 8
- कंजूसीः धन की नहीं... मन की कमी ... 11

स्थानीय परोपकार के पीछे की प्रेरणाएं एवं प्रभाव

'राजस्थान में जमीनी स्तर पर परोपकार की प्रेरणाएं और प्रभाव' परियोजना के तहत 'कट्स' द्वारा अजमेर में 11 नवंबर 2025 को हितधारक परामर्श का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अजमेर मंडल के जमीनी स्तर के परोपकारी, नागरिक समाज संगठन, शिक्षाविद् और रोटरी क्लब के सदस्य आदि शामिल हुए।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर स्थापित परोपकारी गतिविधियों, प्रेरणाओं, सामाजिक प्रभाव और चुनौतियों को समझना था। विषयान्तर्गत की गई चर्चाओं में समुदाय केंद्रित और आवश्यकता आधारित दान, महिला नेतृत्व, पारदर्शिता और स्वयंसेवी-संचालित परोपकार मॉडल के महत्व पर प्रकाश डाला गया। प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, विकलांगता और ऑटिज्म जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान और राजस्थान में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में जमीनी स्तर पर परोपकार की भूमिका को पुनः स्थापित किए जाने पर बल दिया गया।

इसी परिपेक्ष्य में 23 दिसंबर 2025 को जोधपुर में भी हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर परोपकार के प्रभावों की गहरी समझ विकसित करना था। इस परामर्श में जमीनी स्तर के परोपकारी, नागरिक समाज और समुदाय आधारित संगठनों, शिक्षाविदों, रोटरी क्लब के सदस्यों और व्यक्तिगत परिवर्तन कर्ताओं सहित विभिन्न समुदायों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

विषयगत चिंतन और एक खुले संवाद के माध्यम से प्रतिभागियों ने समुदाय नेतृत्व वाले दान के अपने अनुभवों को आपस में साझा किया। कार्यक्रम में महिला नेतृत्व, विश्वास और स्थानीय आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, अपशिष्ट प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य पर संबोधित करते हुए दीर्घकालिक जुड़ाव की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इन चर्चाओं के जरिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, जो अनुसंधान में सहायक और स्थानीय स्तर पर परोपकारी प्रथाओं को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगी।

बाबूलाल कांकरेलिया 'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित

'कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल ग्रामीण पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष उन श्रेष्ठ पत्रकारों को दिये जाते रहे हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मामलों को असरदार तरीके से उठाया है।

इस बार वर्ष 2024 के लिए यह पुरस्कार 'कट्स' द्वारा अजमेर में 'राजस्थान में जमीनी स्तर पर परोपकार की प्रेरणाएं और प्रभाव' परियोजना के तहत आयोजित हितधारक परामर्श बैठक के दौरान जयपुर जिले के भानपुर कलां गांव के मूल निवासी स्वतंत्र पत्रकार बाबूलाल कांकरेलिया को प्रशस्ति पत्र एवं 10 हजार रुपए का चैक प्रदान कर सम्मानित किया गया। कांकरेलिया ने वर्ष 2024 के दौरान 'सेहत पर भारी पैकेट बंद खाद्य पदार्थ एवं प्रोसेस्ड फूड' विषय पर विभिन्न समाचारपत्रों में कई रोचक स्टोरियां प्रकाशित कर आमजन में जागरूकता लाने एवं जनचेतना जागृत करने का काम किया है।

किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा

केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना 'पीएम किसान सम्मान निधि' में बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन ट्रेकिंग और सत्यापन में पता चला है कि देश में 31.01 लाख संदिग्ध लाभार्थी लंबे समय से योजना का गलत फायदा उठा रहे थे। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ।

केंद्र सरकार अब तक ऐसे लोगों से 416 करोड़ रुपए की वसूली कर चुकी है। सभी राज्यों में भी वसूली की प्रक्रिया जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों को संदिग्ध लाभार्थियों के नाम हटाने, नोटिस भेजने तथा फंड रिकवरी के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में सत्यापन शुरू कर दिया गया है। गलत लाभार्थियों से वसूली कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। *(रा.प., 12.11.25)*

पीएम इंटर्नशिप...संसद में दी जानकारी

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक पीएम इंटर्नशिप का एक साल पूरा हो गया। सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार इस एक साल में 1.25 लाख अभ्यर्थियों को उनके कौशल क्षेत्र में पारंगत करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन महज 2066 उम्मीदवार ही एक साल की इंटर्नशिप पूरी कर पाए।

इस दौरान सरकार ने 73.72 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें से 16.62 करोड़ रुपए योजना के विज्ञापन पर खर्च किए गए। गौरतलब है कि 2024-25 के बजट में इस योजना का एलान हुआ था। इसके तहत देश की टॉप-500 कंपनियों में अगले पांच साल के दौरान एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करानी थी। फीडबैक सर्वे में सामने आया कि उम्मीदवार 5 से 10 किमी की दूरी में इंटर्नशिप चाहते हैं। वे सामान्य कौशल के लिए 12 महीने की इंटर्नशिप अवधि भी ज्यादा मानते हैं। *(दै.भा., 03.12.25)*

बच्चों का निवाला छीन रहे हेडमास्टर

राजस्थान के 69 लाख स्कूली बच्चों को रोज दूध देने की 722 करोड़ रुपए की पन्नाधाय बाल गोपाल योजना बच्चों का कुपोषण भले दूर न कर पा रही हो लेकिन ये सरकारी शिक्षकों के भ्रष्टाचार को पोषित कर रही है। भास्कर की टीम ने एक महीने पड़ताल की तो खुलासा हुआ कि बच्चों का दूध पाउडर मावा फैक्ट्रियों मे जा रहा है।

जोधपुर व बालोतरा के तीन स्कूलों में दूध के पैकेट बेचने का खुलासा हुआ। संस्थाप्रधानों ने खुद कबूल किया कि 90 से 100 रुपए किलो के हिसाब से ठेकेदार उनसे दूध ले जाते हैं और ठेकेदार वही दूध पाउडर मावा व्यापारियों को 135 से 200 रुपए किलो में बेचते हैं। इधर स्कूल के बच्चों का कहना है कि उन्हें फरवरी के बाद से ही दूध नहीं मिला। जांच में सामने आया कि बच्चों का निवाला छीनने वाले हेडमास्टरों को शर्म भी नहीं आती। इसी तरह यदि सरकार प्रदेश के स्कूलों में गहन पड़ताल करें तो भ्रष्टाचार की बड़ी पोल सामने आ सकती है। *(दै.भा., 25.10.25)*

करोड़ों रुपए खर्च फिर भी परियोजनाएं रही अधूरी

प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 541 परियोजनाएं अधूरी रह गई। इससे इस राशि का सदुपयोग नहीं हुआ, वहीं राज्य पर ऋण और ब्याज सहित अन्य वित्तीय भार बढ़ गया।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर यह खुलासा किया है। इससे सामने आया कि 34 परियोजनाएं तो ऐसी थीं जो वर्ष 2014-15 से पहिले की होने के बावजूद अब तक पूरी नहीं हो पाई। सीएजी के अनुसार परियोजनाएं अधूरी रहने से राशि अवरोधित हो गई। इन अधूरी परियोजनाओं में खासतौर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की 350, जल संसाधन विभाग की 110 और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की 81 परियोजनाएं हैं। नतीजतन जनता को परियोजनाओं का समय पर लाभ नहीं मिल पाया। *(रा.प., 12.10.25)*

कर्ज के जाल में फंस रहे युवा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुताबिक भारत में कामकाजी लोगों की आय और कर्ज (डेट-टू-इनकम रेश्यो) का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। भारतीय परिवारों की औसतन आय का 40% से ज्यादा हिस्सा कर्ज चुकाने में जा रहा है। शहरी युवाओं में यह अनुपात और भी ज्यादा है। कई मामलों में 50-60% तक है।

ऊंची सेलेरी, शानदार जीवनशैली और कर्ज का यह मेल देश में मिलेनियल्स को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। हर माह लाखों रुपए कमाने के बावजूद वे वित्तीय असुरक्षा में जी रहे हैं। ईएमआइ कल्चर के चलते घर, कार, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, कपड़े, गजेट्स...हर चीज लोग ईएमआइ या बाय नाउ पे लेटर के जरिए खरीद रहे हैं, जिससे आय पहले से ही बंध जाती है। सेबी के मुताबिक 64% भारतीय परिवारों के पास कोई संगठित बचत योजना नहीं है। *(रा.प., 24.11.25)*

कितना गहरा फैला है नशे का जाल?

राजस्थान में नशे का कारोबार किस हद तक फैल चुका है, इसका अंदाजा पुलिस रिकॉर्ड और बरामदी के आंकड़े देते हैं। पिछले तीन वर्षों (2022-2024) में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। महंगा नशा शहरों में व सस्ता नशा गांवों तक युवाओं की जिन्दगी छीन रहा है।

यह सिर्फ तस्करी का फैलता नेटवर्क नहीं, बल्कि गांव-गांव तक सप्लाई चेन और अनजान युवाओं की बढ़ती लत का नतीजा है। नशे की गिरफ्त में आते ही युवाओं का घर परिवार से रिश्ता टूटने लगता है। चोरी, लूट और हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ती है । कई परिवार अपने बेटे और बेटियों को इस दलदल में खो चुके हैं। इलाज के लिए जमीन तक बेच दी गई, लेकिन परिणाम ज्यादातर मामलों में शून्य ही रहा। *(रा.प., 11.12.25)*

सरकार को लगाई 600 करोड़ की चपत

आरटीओ कार्यालयों में हुए थ्री डिजिट नंबरों के फर्जीवाड़े के मामले में गठित जांच कमेटी ने प्रदेश में 10 हजार वीआइपी नंबरों के हेरफेर की आशंका जताई है। कमेटी ने इस फर्जीवाड़े में सरकार को 500 से 600 करोड़ रुपए की राजस्व हानि का होना पाया है।

नपेंगे परिवहन विभाग के 450 अफसर-कार्मिक
राजस्थान सरकार को ऐसे लगाई 600 करोड़ की चपत

रिपोर्ट में बताया गया है कि आरटीओ कार्यालयों में वीआइपी नंबरों को नियम विरुद्ध पंजीयन कर बेच दिया गया। काम को अंजाम देने के लिए आरसी और आधार सहित अन्य जाली, फर्जी इस्तावेज तैयार किए गए। कमेटी ने स्वीकार किया है कि आरटीओ कार्यालयों में कार्मिकों ने फर्जीवाड़ा कर गंभीर अपराध किया है। कमेटी ने प्रकरण की जांच अब एसओजी से कराने की सिफारिश की है। परिवहन विभाग में हुए इस फर्जीवाड़े में अब ईडी की एंट्री भी हो गई है। ईडी ने परिवहन विभाग से जांच रिपोर्ट मांगी है। *(रा.प., 02.11.25)*

मरीजों तक पहुंच रही नकली दवा

प्रदेश में सालाना 20 हजार करोड़ के थोक और खुदरा दवा बाजार में करीब 500 से 600 करोड़ रुपए की दवाइयां अमानक और नकली मिल रही हैं। मरीजों के लिए खतरा बन सकने वाली ये दवाइयां बाजार में जाने के बाद लिए गए सेंपल में घटिया या नकली पाई जा रही हैं।

सैंपल में फेल होने के बाद औषधि नियंत्रण आयुक्तालय इन पर रोक लगाने और बाजार से हटाने की पूरी मिम्मेदारी निर्माता, थोक व खुदरा विक्रेता को देकर मुक्त हो जाता है। इस साल अब तक 98 दवाओं के बैच अमानक, गलती से या जानबूझकर दवा बिकी, वह मरीज की जान पर खतरा बन सकती है। हर साल 125 से अधिक दवाएं अमानक या नकली मिल रही है। कई बार तो दवा की बड़ी मात्रा बाजार में बिक जाने पर उसके अमानक या नकली होने का पता चलता है। *(रा.प., 13.10.25)*

खेल परिषद में करोड़ों का खेल

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट में राजस्थान खेल परिषद के खातों में कई स्तरों पर बड़े पैमाने पर अनियमिताएं सामने आई हैं। जिस संस्था का उद्देश्य खिलाडियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना हो और वहां गड़बड़ी हो तो इसे गंभीर माना जाना चाहिए।

सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2023 के बीच सरकार द्वारा 209.54 करोड़ रुपए की ग्रांट स्पोर्ट्स काउंसिल को दी गई। ऑडिट में स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह धनराशि जिन मदों के लिए जारी की गई, उन्हीं मदों में उपयोग हुई या नहीं। अर्थात 13 वर्षों की ग्रांट के उपयोग का पूरा विवरण अधर में है। संस्था के पब्लिक डिपॉजिट अकाउंट में भी भारी अनियमितता और विसंगतियां मिली। हिसाब-किताब में 38.20 करोड़ रुपए के अंतर का भी कोई जवाब नहीं है। बैंक और खेल परिषद के रिकॉर्ड में भी बडा अंतर सामने आया है। *(दै.भा., 10.12.25)*

करोड़ों मृतकों के आधार 'जिंदा'

देश में हर नागरिक को आधार नंबर जारी करने की शुरुआत को 15 साल हो चुके। इस दौरान 142 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी हुए, लेकिन 8 करोड़ से ज्यादा कार्ड धारकों की मौत के बावजूद 1.83 करोड़ ही निष्क्रिय हो पाए हैं। करीब 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड अभी भी सक्रिय हैं।

इससे बैंक फ्रॉड, फर्जी खातों और सरकारी योजनाओं के लाभ में गड़बड़ी जैसी आशंका बढ़ गई है। यूआइडीएआइ ने हाल ही चार माह पहले वेबसाइट पर-मृत्यु सूचना पोर्टल शुरू किया है, ताकि परिजन मृतक का आधार ऑनलाइन निष्क्रिय करा सके। मृत्यु सूचना के बाद यह देखा जाता है कि कार्ड का बायोमेट्रिक इस्तेमाल तो नहीं हुआ। इसके बाद ही कार्ड निष्क्रिय किया जाता है। अब तक 3000 लोगों ने इसकी जानकारी दर्ज की है। जिसमें से 500 मामलों की ही पुष्टि हो सकी है। *(दै.भा., 13.11.25)*

बच्चों को बना रहे बंधुआ मजदूर

आदिवासी अंचल में बच्चों को गिरवी रख, उन्हें बंधुआ बनाने का भयावह काम बेरोकटोक हो रहा है। गरीब, लाचार परिवार आज भी 8 से 12 साल के बच्चों को 20 से 25 हजार रुपए में गड़रियों के पास एक साल के लिए गिरवी रख रहे हैं। वहीं अधिकतम 40 से 45 हजार रुपए में बच्चे बेचे भी जा रहे हैं।

यह सौदेबाजी मारवाड़ के सिरोही पाली से आने वाले गड़रिये कर रहे हैं। पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले इससे ज्यादा प्रभावित है। पैसा चुकाने के बाद बच्चों को प्रतिदिन 20 से 35 किमी तक भेड़ों के रेवड़ के साथ पैदल चला रहे हैं। वे उन्हें बंधुआ बाल मजदूर बना कर उनका शोषण कर रहे हैं। बच्चों को न भरपूर खाना मिलता है और न ही आराम। बंधुआ बालश्रम केवल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही नहीं, बल्कि यह कानूनन भी गंभीर अपराध है। यह आवश्यक है कि ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई हो। *(रा--.प., 02.10.25)*

दिव्यांगता सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सभी विभागों में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्त कार्मिकों की पुनः दिव्यांगता जांच के आदेश के बाद सरकारी तंत्र में खलबली मच गई है। इस फैसले से प्रदेशभर में कार्यरत 15 हजार से अधिक दिव्यांग कार्मिकों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है।

हाल ही सरकारी नौकरियों में दिव्यांगता सर्टिफिकेट से जुड़े कई फर्जीवाड़े सामने आए हैं। कार्मिकों को आशंका है कि दिव्यांगता में मामूली कमी भी उनकी पात्रता पर प्रश्नचि लगा सकती है। पहले मेडिकल बोर्ड केवल भौतिक परीक्षण के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करते थे, जबकि अब आधुनिक मशीनों और तकनीकी उपकरणों से जांच की जा रही है। अभ्यर्थियों को कहना है कि दिव्यांगता की पुनः जांच कराने के बजाय फर्जी सर्टिफिकेट की जांच करानी चाहिए। *(रा.प., 14.12.25)*

सतत् विकास लक्ष्यों की योजना

हम दुनिया का कायाकल्प करने की दहलीज पर खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत् विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक सम्पन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जाएगा।

गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि और उत्कृष्ट कार्य, बुनियादी सुविधाएं, उद्योग एवं नवाचार, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर, उपभोग व उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक प्रणालियां, शांति एवं न्याय और भागीदारी।

अरावली में खनन पट्टे पर रोक

केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टे जारी करने पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने यह कदम अरावली की पारिस्थितिकी को बचाने के लिए उठाया है। मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् को संरक्षित क्षेत्र बढ़ाने का निर्देश दिया है।

केंद्र सरकार ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् को निर्देश दिए हैं कि वह पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक वैज्ञानिक और समग्र खनन प्रबंधन योजना तैयार करे। इस योजना में पर्यावरणीय प्रभाव, पारिस्थितिकीय क्षमता, संवेदनशील और संरक्षण योग्य क्षेत्रों की पहचान और पुनर्स्थापन के उपाय शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि केंद्र के फैसले के अनुसार अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर प्रतिबंध लगेगा। अतिरिक्त ईको संसेटिव जोन चिन्हित होंगे तथा माइनिंग प्लान तैयार होगा।

(दै.भा. एवं रा.प., 25.12.25)

रिसर्च-इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा

हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाख करोड़ रुपए के रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (आरडीआई) फंड की शुरुआत की है। इस फंड से उच्च स्तर की तकनीकी और जोखिम वाले क्षेत्रों में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग देश के वैज्ञानिकों की क्षमताओं को बेहतर करने के लिए होगा। देश में अनुसंधान और नवाचार के लिए माहौल तैयार किया जाएगा। इक्कीसवीं सदी में दुनिया भर के विशेषज्ञों को साथ आकर विज्ञान, तकनीक और नवाचार पर मंथन करने और मिलकर दिशा दिखाने की जरूरत है। इस कोष का पैसा नए मौके खोलने के लिए है। इसका सीधा असर देश में बनने वाले उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ेगा।

(रा.प., 04.11.25)

राजस्थान बनेगा फूडबास्केट...

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही विकसित राजस्थान-2047 का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। विजन डॉक्यूमेंट में हर गांव तक पानी पहुंचाने, बंजर जमीन का टैग हटाकर देश में प्रदेश को फूड बास्केट बनाने के साथ हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर राजस्थान को अग्रणी बनाने का रोडमैप है।

विजन डॉक्यूमेंट में स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन, पर्यावरण और ग्रामीण व शहरी विकास पर खास नजर रखते हुए बताया गया है कि राजस्थान इस तरह से विकसित होगा। यह सब भले ही सपने जैसा लगे, लेकिन सरकार का दावा है कि प्रदेश को हर क्षेत्र में विकसित एवं अग्रणी बनाया जाएगा। कार्यों में रफ्तार धीमी नहीं पड़े, इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी है।

(रा.प., 24.10.25)

एआई अपनाने में भारतीय सबसे आगे

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल में भारत वैश्विक स्तर पर सबसे आगे निकल रहा है। देश के कर्मचारियों और कंपनियों-दोनों ने ही एआई को उत्पादकता बढ़ाने का सशक्त माध्यम माना है। भारतीय संगठनों में एआई का प्रभाव केवल तकनीक तक सीमित नहीं, बल्कि कार्य संस्कृति को भी बदल रहा है।

ईवाय 2025 वर्क रीइमैजिंड सर्वे के मुताबिक, भारत ने 'एआई एडवांटेज' स्कोर पर 53 अंक हासिल किए हैं, जबकि वैश्विक औसत 34 अंक है। यह स्कोर मापता है कि एआई से कर्मचारियों का कितना समय बचता है। यह देश का 'टैलेंट हेल्थ' स्कोर और विकास को दर्शाता है। नैतिकता को लेकर भी एआई के प्रति भारत में विश्वास देखा गया है। करीब 94% एम्प्लॉयर और 89% कर्मचारी इस पर भरोसा करते हैं। हालांकि 87% कर्मचारी और 90% एम्प्लॉयर नई स्किल सीखने को भी जरूरी मानते हैं। *(रा.प., 26.12.25)*

आपदा प्रभावित देशों में 9वें नंबर पर

जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं पर जर्मन संस्था जर्मन वाच ने अपनी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2026 जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 1995 से 2024 के बीच दुनियाभर में 9700 से ज्यादा चरम मौसम घटनाओं से 8.32 लाख लोगों की मौत हुई, 5.7 अरब लोग प्रभावित हुए व आर्थिक नुकसान 39 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा।

आपदाओं से प्रभावित टॉप 10 देशों में भारत नौवें नंबर पर रहा। वैश्विक स्तर पर बाढ़, तूफान, लू और सूखा सबसे विनाशकारी चरम मौसम घटनाएं रहीं। 1995 से 2024 के बीच हॉट वेव और तूफान से 33%-33% मौतें हुईं, जबकि आर्थिक दृष्टि से तूफानों ने 58% नुकसान पहुंचाया। भारत इस सूची में 9वें स्थान पर है। लंबे समय से टॉप 10 प्रभावित देशों में कोई भी अमीर देश नहीं है।

(रा.प., 13.11.25)

एक दूसरे पर लगाए घूस लेने के आरोप

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आइटीएटी) जयपुर बेंच में रिश्वत को लेकर अपील निपटाने का मामला लगातार गहराता जा रहा है। सीबीआइ ने इस हाई-प्रोफाइल प्रकरण में शामिल चार प्रमुख आरोपियों जूडिशियल मेंबर डॉ. एस सीतालक्ष्मी, एडवोकेट राजेन्द्र सिंह सिसोदिया, अपीलकर्ता मुज्जमिल और मेंबर अकाउटेंट कमलेश राठौड़ को आमने-सामने बैठाकर लंबी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी एक-दूसरे पर संदिग्ध लेन-देन और रिश्वत लेने के आरोप लगाते रहे। इस घूसखोरी में सहायक रजिस्ट्रार केसी. मीना भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

सीबीआई के अनुसार अब तक जांच में 1.40 करोड़ रुपए की रिश्वत का खुलासा हुआ है। एजेंसी आइटीएटी में लंबे समय से सक्रिय भ्रष्टाचार नेटवर्क की गुत्थियों को सुलझाने में जुटी है। सीबीआइ सूत्रों के अनुसार इस मामले में बिल्डर विजय गोयल की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। माना जा रहा है गोयल के सामने आने के बाद रिश्वत के नेटवर्क की कई परतें खुल सकती है।

(रा.प., 29.11.25, 04.12.25)

अभियोजन स्वीकृति नहीं कैसे चले केस

ब्रेन कॉइल के बिल पास करने के बदले एक लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के तत्कालीन प्रभारी डॉ. मनीष अग्रवाल के खिलाफ राज्य सरकार ने अभियोजन की अनुमति नहीं दी है। इसके चलते न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे डॉ.अग्रवाल और सहयोगी जगत सिंह को हाइकोर्ट से राहत मिल गई।

हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा मामले में चालान पेश हो चुका है, लेकिन अभी तक अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली। ऐसे में ट्रायल कोर्ट मामले में प्रसंज्ञान नहीं ले सकती और ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा।

(रा.प., 16.12.25)

पत्नी को दिलवाई फर्जी नियुक्ति

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (डीओआइटी) के अधिकारी प्रद्युमन दीक्षित के खिलाफ राजकाम्प में फर्जी तरीके से पत्नी की नियुक्ति दिखाकर हर महीने 1.60 लाख रुपए वेतन उठाने का मामला सामने आया। चौंकाने वाली बात यह है कि पत्नी को दिए जाने वाले वेतन के बिल पर साइन भी अधिकारी पति करता था।

मामले में परिवादी टी.एन शर्मा ने राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड के संयुक्त निदेशक प्रद्युमन दीक्षित, उनकी पत्नी पूनम दीक्षित और उपनिदेशक राकेश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत की थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसीबी ने जांच के दौरान पूनम दीक्षित के बैंक खातों का रेकॉर्ड जब्त किया है। जांच में प्रद्युमन और पूनम का सयुंक्त बैंक खाता एसबीआई, तिलक मार्ग में मिला है। जिसमें नियमित रकम ट्रांसफर होती रही है।

(रा.प., 26.10.25)

गहराई तक फैली हैं भ्रष्टाचार की जड़ें

भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें गहराई तक फैली हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अनुसार भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है और उसका स्कोर सिर्फ 38 है। यह 2023 के 93वें स्थान (स्कोर 39) और 2022 के 85वें स्थान (स्कोर 40) से गिरावट को दर्शाता है।

इससे साफ है कि भारत में देश-दुनिया दोनों की नजर में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भारत में रिश्वतखोरी उजागर करने पर सुधार की बजाय अकसर प्रतिशोध देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को निराशा तब होती है जब, भ्रष्टाचार के खिलाफ ट्रैप कार्यवाई में रंगे हाथों पकड़े गए अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ विभागों के द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं देने या लेटलतीफी बरतने से भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं।

(रा.प., 17.10.25, 01.11.25)

भ्रष्टाचार की बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली गई राशि	स्त्रोत
जयपुर	चंद्रप्रकाश हैप्पी माथुर	थाना प्रभारी, फुलेरा थाना फिक्सर ?	70,000	दै.भा., 09.10.25
राजसमंद	कमलेश चन्द्र खटीक	भू-अभिलेख निरीक्षक, कुंवारिया तहसील गांव भाणा	7,00,000	दै.भा., 15.11.25
जोधपुर	डॉ. बुधराज बिश्नोई	राजकीय ट्रोमा सेंटर, बिलाड़ा	3,70,000	दै.भा., 15.11.25
जयपुर	राजकुमारी जुनेजा	थानेदार (उपनिरीक्षक) गांधी नगर थाना, जयपुर	1,25,000	रा.प. एवं दै.भा., 20.11.25
बारां	रमेश चंद्र बैरागी	महाप्रबंधक, तिलम संघ, कोटा	30,000	रा.प., 27.11.25
जयपुर	केसी. मीना	सहायक रजिस्ट्रार, आइटीएटी	1,25,000	रा.प., 04.12.25
पाली	भगाराम	एएसआइ, चौकी प्रभारी, पीपलिया कलां, रायपुर	1,00,000	रा.प., 13.12.25
बीकानेर	पुरषोत्तम जोशी	असिस्टेंट ऑफीसर, जीएसटी टैक्स	50,000	दै.भा., 16.12.25
भीलवाड़ा	पंकज छीपा	मेडिकल ऑफीसर, प्राइवेट अस्पताल	11,00,000	दै.भा., 16.12.25

भारत में 'सत्ता समर्थक स्वर्णकाल'

आर्थिक तनाव और सामाजिक उथल-पुथल के कारण जहां वैश्विक स्तर पर 'सत्ता विरोधी' लहर चल रही है , वहीं भारत में पिछले वर्षों से 'सत्ता समर्थक' रुझान के कारण सरकारें लौट रही है। देश के पिछले आम चुनाव में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया।

देश के अन्य कई राज्यों में भी 'सत्ता समर्थक जनादेश' आया। यह स्थिति आजादी के बाद हुए तीन चुनावों की झलक दे रहा है, जब 85 फीसदी सरकारें दोबारा चुनी गई थीं। यह 'सत्ता समर्थक स्वर्णकाल' की वापसी जैसा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में मजबूत नेता-केंद्रित राजनीति और कल्याणकारी योजनाओं में असंतोष को दूर करने में सफलता पाई है। अर्थात, व्यक्तिगत छवि और योजनाओं पर विश्वास जताया गया है। *(रा.प., 29.12.25)*

भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यह निरंतर प्रगति करे, इसके लिए केंद्र सरकार कई नीतिगत कदम उठा रही है। जिनसे युवाओं के लिए भी अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं से कहा कि वे इन अवसरों का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के साथ ही युवाओं के प्रशिक्षण के लिए समुचित कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि युवा उनका भरपूर उपयोग कर सके। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा से कमाए धन को वंचितवर्ग ओर देश की सेवा में भी लगाना चाहिए।

(जा.ज., 11.11.25)

सहकार से समृद्धि की संकल्पना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने में राजस्थान अग्रणी राज्यों में है। राज्य सरकार सहकारी समितियों को सशक्त कर ग्रामीणों की आय बढ़ाने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा किसानों को बेहतर बाजार के अवसर सुनिश्चित कर रही है।

उन्होंने कहा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नवीन को-आपरेटिव अधिनियम से सहकारिता आंदोलन अधिक समावेशी बनेगा। इससे जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नवीन को-आपरेटिव कोड में वे सभी प्रावधान जोड़े जाएं, जिससे सहकारी समितियों को पारदर्शी, आर्थिक रूप से मजबूत एवं सभी के लिए सुलभ बनाया जा सके। *(रा.प., 21.10.25)*

राज्यों की कमाई का लेखा-जोखा

एक दशक से मुफ्त की योजनाएं और सब्सिडी राज्यों की सत्ता पाने का 'शर्तिया नुस्खा' बन रहा है। लेकिन राज्यों की बिगड़ती सेहत इस नुस्खे का बड़ा साइड इफेक्ट बन कर सामने आ रही है। राज्यों के पास बिजली, सड़क आवास आदि के लिए पैसा ही नहीं बचता।

राज्यों की कमाई और खर्च का लेखा-जोखा बताता है कि सब्सिडी वेतन, पेंशन और ब्याज की अदायगी जैसे अहम खर्चों के बाद राज्यों के हाथ अपनी कमाई का 20-25% हिस्सा ही बच पा रहा है। मसलन राजस्थान को इस बार 1.50 लाख करोड़ रुपए कर्ज का मूलधन चुकाना है। इससे भी खराब हाल पंजाब, बंगाल जैसे कई राज्यों का है। मुफ्त की या सब्सिडी की घोषणा करते समय यह देखना जरूरी है कि आय के संसाधन कितने हैं। *(दै.भा., 31.12. 25)*

देश में नई कृषि क्रांति की तैयारी

नीति आयोग ने देश में खेती की दिशा और दशा बदलने के लिए अगले पांच साल के लिए नया रोडमैप तैयार किया है। इसमें कृषि में 100 फीसदी आत्मनिर्भरता लाने के लिए ऐसी तकनीकों को चुना गया है, जिसके जरिए देश की कृषि में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।

चुनी गई ये तकनीकें जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, मिट्टी की थकान और बाजार की अनिश्चितता को खत्म करने में मददगार बनेगी। रोडमेप पर प्रभावी अमल से देश में कृषि लागत 40 प्रतिशत घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब खेती ड्रोन, एआइ और बीजों की जीन एडिटिंग से होगी। पानी की बरबादी शून्य होगी और पैदावार भरपूर हो सकेगी। इससे किसान की आय बढ़ेगी।

(रा.प.,06.11.25)

नीतियों की नई उड़ान, प्रदेश बनेगा विकास का हब

राजस्थान मे लगातार नीतिगत बदलाव का दौर चल रहा है। पहले 22 पॉलिसी में बड़े बदलाव के बाद अब राज्य सरकार 12 और नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसमें कृषि से एयरोस्पेस और एआइ से ग्रीन ग्रोथ तक के सेक्टर शामिल हैं, जिनसे प्रदेश विकास का हब बनेगा।

डिफेंस और एयरोस्पेस के कल पुर्जे भी यहीं बनें, इसके लिए 'आत्म निर्भर भारत डिफेंस नीति' के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर टारगेट किया गया है। इसमें देश विदेश की बड़ी कंपनियों को यहां लाने पर फोकस रहेगा। इसी तरह एआइ और मशीन लर्निंग पर फोकस करते हुए ग्लोबल कैपेबिलेटी सेंटर का नया केंद्र बनाने की दिशा तय की जा रही है, ताकि युवाओं को बेंगलूरु, हैदराबाद आदि स्थानों पर न जाना पड़े।

(रा.प., 04.11.25)

अब छत बनेगी कमाई का जरिया

रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए खुशखबर है। रूफटॉप सौलर पैनल के जरिए बिजली उत्पादन कर डिस्कॉम को सप्लाई करने के बदले उन्हें 25 प्रतिशत ज्यादा भुगतान मिलेगा, जो करीब 55 पैसे प्रति यूनिट होगा। इस निर्णय से 1.36 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।

डिस्कॉम्स ने सोलर एनर्जी के फीड-इन टेरिफ रेट (नेट मीटरिंग) में भुगतान दर 2.71 रुपए से बढ़ाकर 3.26 प्रति यूनिट कर दी है। यानी अब जो उपभोक्ता अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन करते हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देते हैं, उन्हें पहले से ज्यादा दर पर भुगतान किया जाएगा। इसी तरह नेट बिलिंग के उपभोक्ताओं के लिए दर भी 3.04 रुपए से बढ़ाकर 3.65 रुपए यूनिट की गई है। *(रा.प., 05.11.25)*

बिजली दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी

प्रदेश में 1.73 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर है। आगामी वित्त वर्ष में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दरअसल, प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित समय पर अपनी एआरआर (वार्षिक आवृत्ति राजस्व) और टैरिफ याचिका राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के समक्ष 28 एवं 29 नवम्बर को प्रस्तुत कर दी है।

जिसमें इन कंपनियों ने प्रस्तावित दरों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के समान ही रखा है। अब नियामक आयोग विभिन्न पक्षों से सुनवाई के बाद इस याचिका पर अपना निर्णय सुनाएगा और आगामी वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरों का निर्धारण करेगा। *(दै.भा., 06.12.25)*

ऊर्जा मानचित्र पर बढ़ेंगे नए कदम

प्रदेश जल्द ही देश के ऊर्जा मानचित्र पर एक और बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। बीकानेर में देश का अब तक का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट (संयुक्त) स्थापित किया जाएगा। प्रोजेक्ट की कुल क्षमता 2450 मेगावाट सोलर उत्पादन और 5000 मेगावाट-ऑवर बैटरी स्टोरेज की होगी।

इस पर 15 से 17 हजार करोड़ रुपए के बीच लागत आने का अनुमान है। इससे न केवल सस्ती बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि उसे स्टोर भी किया जाएगा, ताकि जरूरत के समय पर इसका उपयोग किया जा सके। खास बात यह है कि ईआरसीपी के बाद यह प्रोजेक्ट प्रदेश की सबसे बड़ी योजना में शामिल होगा। इस नए सिस्टम से दिन में बनी सोलर बिजली बैटरियां स्टोर हो सकेंगी और शाम व रात जैसे पीक समय पर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

(रा.प., 08.11.25)

थर्मल प्लांटः मिलेगा राजस्व व रोजगार

राज्य ऊर्जा विकास निगम ने 3200 मेगावाट क्षमता का नया थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रोजेक्ट स्थापित होने से राजस्थान को आर्थिक, औद्योगिक और रोजगार के स्तर पर बड़ा लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के बजाय अब राजस्थान में ही प्लांट लगने से इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लागत में प्रति यूनिट करीब 18 पैसे की बचत हो सकेगी। साथ ही राज्य में 10 से 15 हजार लोगों को रोजगार व उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। प्रोजेक्ट की लागत 32000 से 38400 करोड़ रुपए के बीच होगी। इससे राज्य को 2880 से 3456 करोड़ रुपए एसजीएसटी राज्य वस्तु एवं सेवा कर) मिलेगा। संचालन के दौरान भी हर वर्ष करीब 173 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कोयले, रखरखाव व अन्य उत्पाद पर टैक्स के रूप में मिलेगा। *(रा.प., 11.10.25)*

फ्री बिजलीः पूर्व रजिस्टर्ड को फायदा

पदेश में 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए करीब 2 लाख 48 हजार 319 उपभोक्ताओं ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया, लेकिन डिस्कॉम की ओर से मात्र 1700 उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी मिल सकी है। इन उपभोक्ताओं को 2.50 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी जा चुकी है।

रजिस्ट्रेशन के बाद 7500 उपभोक्ताओं ने प्लांट लगवा लिया है। हालांकि एक सप्ताह पहले केवल जयपुर डिस्कॉम के 169 लाभार्थियों के बैंक खातों में ही सब्सिडी ट्रांसफर हो सकी थी। लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मीटिंग के बाद डिस्कॉम ने सब्सिडी ट्रांसफर की गति बढ़ाई है। सब्सिडी जारी नहीं होने की वजह से उपभोक्ताओं को 150 यूनिट की बिजली का फायदा भी नहीं मिल पा रहा था। *(दै.भा., 26.12.25)*

सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर

रिन्युएबल एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और 125 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि गैर-जीवाश्व ईधन स्त्रोतों में देश में कुल स्थापित बिजली क्षमता 50 प्रतिशत को पहले ही पार कर चुकी है।

भारत ने अगस्त के अंत तक कुल 192 गीगावाट रिन्युएबल एनर्जी स्थापित क्षमता प्राप्त कर ली है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत 500 गीगावाट ऊर्जा की क्षमता तक पहुंच जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा ऐजेंसी के अनुसार, भारत ने 108 गीगावाट सौर ऊर्जा का प्रभावशाली उत्पादन किया है। दुनिया में सौर ऊर्जा में चीन 887 गीगावाट के साथ पहले स्थान पर और अमरीका 177 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है। *(रा.प., 12.10.25)*

सरकारी छूट.. जमा नहीं करा रहे बिल

प्रदेश में 15 हजार लीटर पानी का शुल्क माफ होने के बाद भी जल उपभोक्ता जलदाय विभाग का बिल जमा नहीं करवा रहे हैं। अकेले जयपुर शहर में उपभोक्ताओं पर 322 करोड़ रुपए बकाया है। विभाग की ओर से नोटिस, चेतावनी व कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई, लेकिन बकाया राशि जमा नहीं हो पा रही।

विभाग कई बार रिकवरी अभियान भी चला चुका है, लेकिन वसूली नहीं कर पाया। यहां तक कि शहरी सरकार, नगर पालिका व नगर परिषदों पर 200 करोड़ से ज्यादा का बकाया चल रहा है। लेकिन जलदाय विभाग सिर्फ नोटिस देकर खानापूर्ति कर लेता है। ऐसे में पानी का बकाया बिल जमा नहीं हो पा रहा है और सरकार को रोजाना करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है।

(दै.भा., 06.12.25)

बह गया 3 बार बीसलपुर जितना पानी

जलदाय विभाग के बीसलपुर बांध में जल भराव व जल निकासी के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष मानसून बिदा होने के बाद बांध 89 दिनों तक ओवरफ्लो रहा और इस दौरान 129.56 टीएमसी पानी की निकासी हुई।

इस निकासी किए पानी से तीन बार बीसलपुर बांध और 11 बार ईसरदा बांध भर सकते थे। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद बीसलपुर से जयपुर तक नई पाइप लाइन बिछाने की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनने का काम अब तक शुरू नहीं हुआ। वित्त समिति की बैठक तो हुई, लेकिन डीपीआर को लेकर क्या निर्णय हुआ, इस पर विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। शहर के 40 प्रतिशत इलाके अभी भी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। कई क्षेत्रों में सप्लाई के दावे और वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर नजर आता है।

(रा.प., 23.10.25)

हर माह 250 अरब लीटर पानी चोरी

जलदाय विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जयपुर शहर में 5 लाख पंजीकृत पेयजल उपभोक्ता हैं, वहीं अलग-अलग इलाकों में एक लाख से ज्यादा अवैध कनेक्शन भी हैं। विभाग के अधिकारियों का ही अनुमान है कि इन अवैध कनेक्शनों से प्रतिमाह पंजीकृत उपभोक्ताओं के हक का 250 अरब लीटर पानी चोरी किया जा रहा है।

इसी वजह से बीसलपुर सिस्टम से पूरा पानी मिलने के बाद भी पंजीकृत उपभोक्ता पूरे साल बूंद-बूंद पानी का संकट झेलने को मजबूर हैं। शहर में बड़े स्तर पर पानी चोरी रोकने को लेकर कनिष्ट अभियंता से लेकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता तक गंभीर नजर नहीं आते। हो हल्ला मचता है तो अवैध जल कनेक्शन काटने की चर्चा होती है, जो बैठकों तक सीमित हो कर रह जाती है। *(रा.प., 28.11.25)*

जल प्रबंधन पर हुई संसद में चर्चा

संसद में राजस्थान से जुड़ी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (संशोधित पीकेसी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के सवाल पर केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि परियोजना की डीपीआर राजस्थान द्वारा तैयार कर ली गई है और आगे तकनीकी व आर्थिक मूल्यांकन के लिए केंद्रीय जल आयोग को भेजी गई है।

जल संरक्षण पर राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में जलशक्ति मंत्रालय ने बताया कि भू-जल प्रबंधन और डिजिटल निगरानी कार्यक्रम सात राज्यों की 8203 ग्राम पंचायतों में लागू है। इनमें 23,000 डिजिटल जल-स्तर रिपोर्टिंग केंद्र संचालित हो रहे हैं। *(रा.प., 03.12.25)*

बिना अनुमति नहीं खुदेंगे ट्यूबवेल

प्रदेश में अब बिना अनुमति के भू-जल दोहन के लिए ट्यूबवेल और कुएं नहीं खोदे जा सकेंगे। भू-जल दोहन के लिए राजस्थान भू-जल प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। बिना अनुमति ट्यूबवेल खोदने वालों पर जुर्माना और जेल की सजा होगी।

भूजल दोहन के नियमों की पहली बार अवहेलना पर 50 हजार रुपए और दोबारा अवहेलना पर 6 माह जेल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने भू-जल प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश में भू-जल दोहन पर निगरानी के लिए राजस्थान भू-जल प्राधिकरण का गठन किया गया है। हालांकि, लोक हित यानी कृषि व घरेलू पानी के लिए ट्यूबवेल खोदने व पानी निकालने के लिए लाइसेंस व एनओसी की जरूरत नहीं होगी। *(दै.भा., 10.10.25)*

भू-जल रिचार्जः अब बरसाती पानी नहीं होगा बेकार

अब जयपुर में भी चेन्नई की तर्ज पर बरसात के पानी से भू-जल रिचार्ज किया जाएगा। जेडीए ड्रेनेज सिस्टम के साथ वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं विकसित करेगा। इससे ड्रेनेज में बहने वाले बरसाती पानी का पहले भू-जल रिचार्ज किया जाएगा और उसके बाद पानी आगे बढ़ेगा।

इस योजना की शुरूआत जोन 6 में बन रहे ड्रेनेज प्रोजेक्ट से की जाएगी। जिसके लिए जेडीए वर्क ऑर्डर जारी कर चुका है। यह ड्रेनेज कालवाड़ रोड से शुरू होगा और खिरणी फाटक होते हुए खातीपुरा पुलिया तक जाएगा, जिसके बाद इसे द्रव्यवती नदी से जोड़ा जाएगा। मार्ग में दो प्रमुख सेक्टर सड़कों पर जल भराव वाले क्षेत्रों को भी इस ड्रेनेज से जोड़ा जाएगा। इसमें 1100 घनमीटर क्षमता वाले मॉड्यूलर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए जाएंगे। छोटे स्ट्रक्चर ड्रेनेज के किनारे-किनारे विकसित किए जाएंगे। इस प्रोजक्ट पर 25.75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। *(रा.प., 25.11.25)*

महिलाओं में बढ़ेगा उद्यमिता कौशल

महिलाओं में उद्यमिकता कौशल को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। योजना में महिलाओं को उद्योग, सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित उद्यमों सहित कई क्षेत्रों में ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

योजना के तहत व्यक्तिगत महिला उद्यमियों व महिला स्वयं सहायता समूहों को 50 लाख रुपए तक और महिला स्वयं सहायता समूह कलस्टर और फेडरेशन को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण किफायती दरों पर मिलता है। साथ ही, ऋण राशि का 25 फीसदी अनुदान के रूप में दिया जाता है। योजना में वंचित वर्ग की महिलाओं को 30 फीसदी तक अनुदान देने का प्रावधान है। *(रा.प., 03.11.25)*

बाल विवाह नहीं, अब शिक्षा पर फोकस

यह खुश खबर है, राजस्थान में बाल विवाह की रीत टूट रही है। शिक्षा में बढ़ोतरी, जागरूकता, स्वास्थ के प्रति सजगता और सरकारी प्रयासों से बाल विवाह के खिलाफ बेटियों में जागृति आई है। किशोरियां अपनी मर्जी के खिलाफ बाल विवाह का दंश झेलने को तैयार नहीं। किशोरियां खुद शिकायत कर शादी रुकवा रही हैं।

प्रदेश में 52 बाल विवाह शून्य करवाए गए व 2200 से अधिक बाल विवाह रुकवाए गए हैं। यहां तीन दिन में दो बाल विवाह निरस्त करवाने का रिकॉर्ड बना है। बेटियों की आवाज अदालत तक पहुंच रही है। जोधपुर संभाग में बेटियों ने सबसे ज्यादा बाल विवाह शून्य करवाए है। मेवाड़ की बेटियों ने भी खास हिम्मत दिखाई है। देशभर में प्रदेश बाल विवाह शून्य करवाने में पहले स्थान पर है। *(रा.प., 05.10.25)*

महिला किसानों को मुफ्त बीज किट

राजस्थान सरकार की बीज मिनी किट योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। कृषि और सिंचाई विभाग की ओर से चलाई जा रही इस योजना के तहत कृषक परिवार की महिला सदस्य को बीज मिनी किट उपलब्ध कराई जाती है।

योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, लघु एवं सीमांत किसानों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले किसान परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए कृषक परिवार को अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करना होगा। कृषि पर्यवेक्षक अधिकारी ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर पात्र महिलाओं की सूची तैयार करता है। *(रा.प., 19.12.25)*

निवेश के नए दौर में महिलाएं आगे

महिलाएं अब वित्तीय रूप से पहले से कहीं अधिक जागरूक हो रही हैं। निवेश को लेकर उनके नजरिए में बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां महिलाएं सिर्फ गोल्ड में निवेश करती थी, वहीं अब रियल एस्टेट क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है।

सरकार की मददगार योजनाओं की वजह से प्रॉपर्टी खरीदने में भी महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। इसके लिए उन्हें कई विशेष सुविधाएं दी जाती है। इनमें स्टॉम्प ड्यूटी में छूट, कम ब्याज दर पर होम लोन एवं लोन एप्रूवल में प्राथमिकता जैसी सहूलियतें शामिल हैं। प्रीमियम और लग्जरी प्रॉपर्टी सेगमेंट में सरकारी योजनाएं और बैंकिंग सुविधाएं इस रास्ते को आसान बना रही है। एक्सपर्ट महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई हैं। *(रा.प., 25.11.25)*

मैन्यूफैक्चरिंग में आगे बढ़ी महिलाएं

राजस्थान की महिलाएं अब घर और खेत की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। उनके कदम अब उद्योग और व्यापार क्षेत्र में पुरुषों के बराबर पहुंच गए हैं। उत्पादन के क्षेत्र में तो ये अब पुरुषों से भी आगे बढ़ चुकी हैं।

केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के नए आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्ष में महिला स्वामित्व वाली छोटी व मध्यम इकाइयों की हिस्सेदारी लगभग 6 फीसदी बढ़ी है। प्रदेश में मैन्यूफैक्चरिंग में स्थापित होने वाली हर दूसरी इकाई का नेतृत्व महिला कर रही है। उद्योगों में अब 52% से ज्यादा इकाइयों की मालिक महिलाएं हैं। *(दै.भा., 11.10.25)*

'लखपति दीदी' बन रही उभरती पहचान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजीविका हमारी बहनों के सशक्तीकरण, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की अहम कड़ी के साथ ही गांवों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम बन रहा है। सरकार का संकल्प है कि 'हर हाथ को हुनर, हर घर को रोजगार' मिले।

जयपुर में ओटीएस में लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि लखपति दीदियां अग्रणी राजस्थान की उभरती हुई पहचान बन चुकी है और अगला लक्ष्य मिलेनियर बनना है। इसमें राजीविका सबसे प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है। अब तक प्रदेश में 19.45 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाली लखपति दीदियों को टैबलेट वितरित किए। *(रा.प., 22.12.25)*

देश में आदिवासी बच्चे बनेंगे सक्षम

देश के एकलव्य आवासीय विद्यालयों में पढ़ रहे 9वीं से 12वीं तक के आदिवासी बच्चों को निःशुल्क विशेष कक्षाएं लगाकर 'मिशन सक्षम' के तहत जेईई व नीट की तैयारी करवाई जाएगी।

चयनित बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। मिशन का उद्देश्य आदिवासी बच्चों की एक पीढ़ी को गरीबी से बाहर लाकर सशक्त बनाना है। पहली बार शुरू इस मिशन के तहत 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 630 एकलव्य विद्यालयों के 30 हजार बच्चों को इसकी तैयारी कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका जिम्मा नवोदयन फाउंडेशन ने लिया है। परीक्षा में सफल छात्रों को टॉप मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश दिलवाया जाएगा। *(रा.प., 02.10.25)*

सड़क सुरक्षाः चुप रहना मुमकिन नहीं

राजस्थान की सड़कों पर रफ्तार अब मंजिल तक नहीं पहुंचा रही, सड़क हादसे कई जिंदगियों को बीच रास्ते में ही रोक रहे हैं। सितंबर अक्टूबर के दो महीनों में सड़क हादसों की संख्या और उससे होने वाली मौतों में चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सितंबर में जहां 790 हादसों में 354 लोगों की जान गई, वहीं अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़कर 764 हादसों में 436 मौतों तक पहुंच गया। दौसा, नागौर, बाड़मेर, डूंगरपुर, और श्रीगंगानगर जिलों में सबसे अधिक दुर्घटनाएं और मौतें दर्ज की गई। जयपुर में अक्टूबर में 6 हादसे हुए जिसमें आठ लोगों की मृत्यु हो गई। *(रा.प., 05.11.25)*

सड़क हादसों से हर साल हो रही 1.8 लाख मौतें

देश में सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें 1.8 लाख लोगों की जान चली जाती है। इसमें 66% मौतें 18 से 34 वर्ष की उम्र के युवाओं की होती हैं।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के सवाल पर गडकरी ने स्वीकार किया कि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और कानून सख्त करने के बावजूद सरकार मौतों की संख्या घटाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। हालांकि, केंद्र सरकार राज्यों को आधुनिक एंबुलेंस देने की योजना बना रही है, लेकिन शर्त यह होगी कि एंबुलेंस 10 मिनट के भीतर हादसे की जगह पहुंचे। उन्होंने कहा समय पर इलाज मिलने से जानें बचाई जा सकती थीं। *(दै.भा., 18.12.25)*

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में हेलमेट, लेन ड्राइविंग, अनधिकृत हूटर के मामले में सख्ती बरतने तथा पैदल यात्रियों की दुर्घटना से सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सड़क सुरक्षा के हित में मोटर वाहन कानून के तहत अनुशासन लाने और नेशनल हाईवे से अलग अन्य सड़कों के डिजाइन, निर्माण व रखरखाव मानकों के नियम बनाने के निर्देश दिए हैं।

जस्टिस जेबी पारदीवाला व केवी विश्वनाथन की बेंच ने 13 साल पुरानी याचिका की सुनवाई के बाद जारी आदेश में नियम बनाने के लिए छह माह का समय दिया है। आदेश के अमल के बारे में सात माह बाद सुनवाई की जाएगी। यह याचिका प्रमुख हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. एस. राजशेखरन ने दायर की थी। *(रा.प., 08.10.25)*

रफ्तार सीमा स्पीडो मीटर में 240 क्यों?

तेजी से बनती सड़कों ने मौत की रफ्तार भी बढ़ा दी है। साल-दर-साल वाहन निर्माता अपनी गाड़ियों की रफ्तार अव्यावहारिक सीमा तक बढ़ा रहे हैं। इससे आम लोगों के लिए मौत का फासला कम होता जा रहा है। देश में कुछ एक्सप्रेसवे पर गति सीमा जरूर 110 या 120 किमी/घंटा है पर अधिकतर सड़कों पर 60 से लेकर 100 किमी/घंटा की रफ्तार से ज्यादा गति प्रतिबंधित है।

ऐसे में सवाल उठता है कि वाहन निर्माता कंपनियां ऐसी गाड़ियां क्यों बना रही हैं, जिनके स्पीडोमीटर टॉप स्पीड 240 बता रहे हैं। ग्राहक को रफ्तार के नाम पर लुभाने के लिए सड़कों को रेस ट्रैक में क्यों बदला जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 में सड़क हादसों में 1,77,177 लाख नागरिकों के मरने की जानकारी लोकसभा में दी। केवल चार साल पहले के मुकाबले 21,555 ज्यादा नागरिक मारे गए। वर्ष 2023 के मुकाबले भी 3,351 मौतें बढ़ी...। *(रा.प., 22.12 25)*

तेज स्पीड से वाहन चलाने पर सख्ती

जयपुर शहर में लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने तेज गति से वाहन चलाने वालों पर सख्ती कर दी है। शहर में 60 किमी प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से कार या बाइक चलाने वालों पर पुलिस एफआईआर दर्ज कराएंगी और वाहन जब्त करेगी।

टैफिक पुलिस ने गूगल से टाइअप किया है। गुगल मैप अब रूट के साथ स्पीड लिमिट भी दिखाएगा। वाहन की रफ्तार 55 किमी/घंटा होते ही मोबाइल पर अलर्ट आएगा। एक नवम्बर तक चले ट्रायल के बाद इसे अब लागू कर दिया गया है। गौरतलब है कि शहर में कार बाइक की स्पीड 60 किमी और भारी वाहनों की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा होगी। *(दै.भा., 6.11.25)*

कंजूसीः धन की नहीं... मन की कमी

राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार के पास तो खजाना भरा है, लेकिन जनता की जान बचाने के लिए उस पैसे का उपयोग करने में नौकरशाही की सुस्ती और लालफीताशाही ने सारी योजनाओं की रफ्तार रोक दी है। विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार सड़क सुरक्षा कोष में राशि हर साल बढ़ती जा रही है।

हालात यह हैं कि राज्य सरकार के पास सड़क सुरक्षा कोष में 39 हजार 266 करोड़ रुपए जमा है, लेकिन इनमें से खर्च का आंकड़ा 'तिनका भर' भी नहीं है। फाइलों में उलझी स्वीकृतियां और विभागों के बीच समन्वय की कमी ने यह स्थिति बना दी है कि स्वीकृति का एक तिहाई भी हिस्सा खर्च नहीं हो पा रहा है। पिछले तीन सालों में सुरक्षा कोष से सरकार ने विभिन्न कार्यों के लिए 252 करोड़ 16 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, लेकिन खर्च केवल 69.41 करोड़ रुपए ही हो पाए हैं। यह राशि कुल स्वीकृति का मात्र 27% है। *(रा.प., 09.10.25)*

उपभोक्ता फैसले

उर्वरक कम तोला, विक्रेता और कंपनी को देना होगा हर्जाना

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय में किसान प्रदीप कुमार चौधरी ने वकील के मार्फत अपने गांव की दुकान ईको ट्रेडिंग कंपनी एवं उर्वरक उत्पादक कंपनी के खिलाफ 21 जून 2024 को परिवाद दर्ज कराया। मामले के अनुसार किसान प्रदीप कुमार चौधरी ने इको ट्रेडिंग कंपनी से भारतीय किसान जन उर्वरक शक्ति एनपी के 50 किलो के तीन बैग खरीदे थे। प्रत्येक बैग की कीमत 1,470 रुपए थी। लेकिन प्रत्येक बैग में 50 किलो उर्वरक की बजाय केवल 46 किलो उर्वरक ही निकला। इससे विक्रेता द्वारा उनसे 353 रुपए अधिक लिए गए।

मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रत्येक बैग में 50 किलो के उर्वरक की जगह 46 किलो देकर पूरी कीमत वसूलने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और सेवा दोष माना। आयोग ने विक्रेता और कंपनी पर 85 हजार रुपए का हर्जाना लगाया साथ ही किसान प्रदीपकुमार चौधरी को अधिक वसूली गई राशि 353 रुपए ब्याज सहित वापस देने का आदेश दिया। *(रा.प.,12.10.25)*

ऑपरेशन के बाद आंख की रोशनी गई, अस्पताल को देना होगा मुआवजा

सीकर जिले के गांव जोगियों का बास निवासी श्रीराम ने जिला उपभोक्ता आयोग, झुझुनूं में सेठ आनंदराम जयपुरिया नेत्र अस्पताल, स्टेशन रोड, नवलगढ़ और चिकित्सक डॉ.ईसरत सदानी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। मामले के अनुसार परिवादी श्री राम ने वर्ष 2012 में उक्त नेत्र अस्पताल में उपचार कराया था। ऑपरेशन के बाद उनकी आंख में तेज दर्द, सूजन और दिखाई देने में परेशानी बनी रही। अस्पताल में लंबे इलाज के बावजूद सुधार नहीं हुआ और आंख की रोशनी चली गई। जब परिवादी ने जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल में जांच कराई तो चिकित्सकों ने बताया कि आंख में लेंस गलत लगाया है।

उपभोक्ता आयोग में मामले की सुनवाई पर अस्पताल की ओर से अनुभवी डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन करने, मरीज के आंख मसलने, समय पर दवा नहीं लेने के कारण आंख की रोशनी जाने जैसी कई दलीलें दीं। आयोग ने दस्तावेजों के आधार पर दी गई दलीलों को खारिज कर दिया। उपभोक्ता आयोग ने इसे 'सेवादोष'और चिकित्सीय लापवाही मानते हुए उक्त नेत्र अस्पताल एवं चिकित्सक को संयुक्त रूप से 6 लाख 50 हजार रुपए का मुआवजा मय 6 फीसदी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। *(रा.प., 26.10.25)*

मिलेगी विकसित भारत की यात्रा को तेज गति

बदलाव का कदम...श्रम क्षेत्र में बड़ा सुधार... नया लेबर कोड लागू

केंद्र की मोदी सरकार ने देश में नई श्रम संहिता (लेबर कोड) को लागू कर दिया है। इससे निजी और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगार लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमेव जयते का नारा देते हुए इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि इससे विकसित भारत की यात्रा को तेज गति मिलेगी। लेबर कोड में अनिवार्य नियुक्ति पत्र, न्यूनतम और समय पर वेतन की गारंटी और एक साल में ही ग्रेच्युटी भुगतान की व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ईएसआइसी सुविधा और 40 साल की सेवा के बाद अनिवार्य स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।

श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने नया लेबर कोड लागू करने की घोषणा करते हुए कहा कि ये बदलाव साधारण बदलाव नहीं है पीएम मोदी द्वारा श्रमवीरों के कल्याण के लिए लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है। इससे करीब 40 करोड़ लोगों को फायदा होगा। नए लेबर कोड में महिलाओं के लिए खास सुविधाएं जोड़ी गई है वहीं खतरनाक व जोखिम वाले उद्योगों, गिग वर्कर्स, खनन श्रमिकों, टैक्सटाइल श्रमिकों और आइटी क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं। सरकार का दावा है कि लेबर कोड में श्रम कानूनों को वैश्विक मानदंडों के समान लाने के प्रयास किए गए हैं।

स्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)